

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Hon. Speaker, Sir, as we all know, Kolkata Metro started its operations in 1984 and is India's oldest metro service. During this period of time, we have experienced many suicides and suicidal attempts in the Metro. A large portion of the Kolkata Metro runs through the parliamentary constituencies of Kolkata Dakshin, Kolkata Uttar and Jadavpur. So, I would like to request the hon. Minister to look into this matter very seriously and take immediate steps to introduce platform screen doors at all the Kolkata Metro stations to enhance the safety and security of the people.

Thank you.

SHRIMATI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Hon. Speaker, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak for the first time in this august House.

I would also like to thank our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* for encouraging and giving a 26-year old woman representing the tribal community a chance to contest elections.

I wholeheartedly thank the people of my constituency Araku also for showing immense faith in a young person like me.

As I said earlier, I represent the Araku constituency which is a reserved constituency. We have huge reserves of mineral wealth which have been exploited for so many years. As a result, the lives of the poor tribal people have not improved considerably and the forests, being the main source of their livelihood, are being lost at a rapid rate.

There was a proposal to start a bauxite mine which again would displace a large number of people. I specially thank our CM, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* for putting that project on hold. I request the hon. Environment Minister to evaluate the loss of livelihood of tribal community before granting clearance to the mining project.

In my constituency, there is dire lack of drinking water facilities and this seriously affects the health of the people living in my constituency. I humbly request through you, Sir, the hon. Minister for Drinking Water to include my constituency under the available scheme of Comprehensive Drinking Water Project to improve the drinking water facilities in my constituency at the earliest in this financial year itself.

Thank you.

श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल (महेसाणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नये सांसदों को बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री और श्री अमित भाई का भी आभार मानती हूँ...(व्यवधान)

(1305/PC/RBN)

मैं अपने राष्ट्रीय एवं राज्य नेतृत्व, जिसने मुझे सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, मैं उसकी भी आभारी हूँ। मैं अपने मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर के बड़े बहुमत से जिताया और मुझे सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। ... (व्यवधान)

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महेसाणा में गांवों में रहने वाले निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उक्त जिले में सर्व-सुविधा युक्त वैलनेस सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं अन्य भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रणालियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, ताकि लोग आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें।

हम मानते हैं कि 'प्रिवेंशन इज़ बैटर देन क्योर'। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि महेसाणा में एक सर्व-सुविधा युक्त वैलनेस सेंटर शीघ्र ही खोला जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं श्री नारणभाई काछड़िया को श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गोमती साय जी तीन बार जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार अपने लोक सभा क्षेत्र रायगढ़, छत्तीसगढ़ से चुनकर आई हूँ। मैं अपने क्षेत्रवासियों का इस सभा के माध्यम से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जशपुर की निवासी हूँ। जशपुर बालासाहेब देशपांडे और कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी की कर्मभूमि रही है। जशपुर अत्यंत पिछड़ा जिला है, जहां बहुतायत राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा समाज के लोग भी निवास करते हैं। जिला जशपुर रेल लाइन से अछूता रहा है, जबकि जशपुर झारखंड की राजधानी रांची, ओडिशा के औद्योगिक नगर राउरकेला एवं मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ के बीच में बसा हुआ है। हमारा जशपुर पूरे छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के मामले में टॉप पर है। बोर्ड की परीक्षा में यहां के छात्र-छात्राएं टॉप 10 में आते हैं। हमारे यहां पाठ में आलू और मिर्च की तथा पत्थलगांव क्षेत्र में टमाटर की बंपर

खेती होती है। इतना सब होने के बावजूद भी जिला जशपुर रेल लाइन से अछूता रहा है। आदरणीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने वर्षों से रेल लाइन लाने हेतु प्रयास किया था।

मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ एवं जशपुर में कोरबा से लोहरदगा तक रेल लाइन स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती गोमती साय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हंस राज हंस जी भी पहली बार बोलेंगे। हंस जी सूफी संत हैं, कभी आप सबको भी सुनाएंगे। हंस जी सूफी भजन भी गाते हैं और संत भी हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबके पास समय होगा, तो प्रोग्राम कराएंगे।

...(व्यवधान)

श्री हंस राज हंस (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रिया। हुजूर आपकी मेहरबानी, मैं पहली बार चुनकर आया हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी हल्के से मुझे चुना गया। मैं अपने महबूब नरेन्द्रभाई मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ...(व्यवधान) मेरे इलाके के बहुत सारे मरहले हैं, मसले हैं, लेकिन मैं पहली बोल रहा हूँ, तो सोचता हूँ:

वस्ल की शब न छेड़ूंगा किस्सा-ए-गम,
ये किसी और दिन सुना लूंगा।

मेरे सदगुरु, मेरे बाबाजी ने मुझे एक प्रेयर सिखाई थी, मैं वह आपसे शेयर करता हूँ। शायद वह आप सब के काम आए। ये बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मेरे वतन के रहनुमा बैठे हैं। पहले इनको भी दर्जा-बदर्जा बाअदब, प्रणाम, नमस्कारम, चरण स्पर्शा। वह प्रेयर है:-

ज़िदगी दी है, तो जीने का हुनर भी देना
पांव बख्शे हैं, तो तौफीक-ए-सफर भी देना,
गुफ्तुगू तूने सिखाई है, कि मैं गूंगा था,

अब मैं बोलूंगा, तो बातों में असर भी देना।

(1310/SPS/SM)

मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे।
मेरे भगवान मुझे जज्बात पर काबू दे दे।
मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं।
और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे।

हुजूर पंजाब की सरजमीं में मेरा जन्म हुआ। वह इतनी जरखेज धरती थी। कहते थे कि बंदे को मारकर भी वहां दबा दो तो वह जिंदा हो जाता था। आह! किसी की नजर लग गई। वह धरती न हम बचा सके, पानी हम न बचा सके, जवानी हम न बचा सके। वह पहले आतंकवाद की शिकार हो गई, फिर नशे की शिकार हो गई। वह धरती जिस पर गुरु नानक साहब, जगतगुरु हमारे बड़े साहब ने कहा था “नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात”। यहां सूफियों ने नारा लगाया था कि-

न मैं मस्त हूं, न हूं शराबी मुझे मैकदे की खबर नहीं,
तेरे इश्क ने वह नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया।

जहां नाम की मस्ती थी वहां लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। कहते हैं कि मुकाम किसका था, मुकीम कौन हुआ। मैं दिल्ली आ गया। सर, उत्तर पश्चिमी हल्के में भी यही हाल है। नौजवान, बच्चे ड्रग्स की लत में जा रहे हैं। स्कूलों के इर्द-गिर्द भी ड्रग्स बिक रही है। मैं सारे रहनुमाओं को विनती करता हूं कि पुरजोर कोशिश करें, इस जवानी को बचाएं, अपने फ्यूचर को बचाएं। सरकार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मेहबूब प्रधानमंत्री साहब गरीबों की बात करते हैं। एक लता जी का गाना था—

बुझे तो ऐसे जैसे किसी गरीब का दिल,
जले तो ऐसे जैसे चिराग जलते हैं।

गरीब आदमी मर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। शुक्र करो उन्होंने फिक्र की है, वह कंसर्ण्ड हैं। मेरी अर्जी यही है, गौर से सुनिएगा, लोगों की हालत यह है कि-

चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से,
सब लोग कह रहे थे कि कुछ खा कर मर गया।

ऐ लोगों उन गरीबों की फिक्र करो। मैं उस समाज की बात करता हूं जो गरीब नहीं, अति गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, गटर में मर रहे हैं। मैं सफाई सेवकों की बात करता हूं। उनके लिए हां का नारा लगाओ।

वह रोज मरते हैं, लेकिन उन्हें हर्जाना नहीं मिलता है। कोई एक्सीडेंट में मर जाए, तो करोड़ों रुपया दिया जाता है। उनके नौजवान बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। आखिर में, मैं यह बात करना चाहूंगा कि माननीय अमित शाह साहब ने बोला था कि कश्मीर जम्मू से सूफी किधर गए। मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूं कि सूफीयज्म क्या है। सूफीयज्म यह है कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। ए लोगों मौत याद रखो। इस मिट्टी में कुछ दफन हो जाएंगे, कुछ का संस्कार हो जाएगा। जात धर्म मजहब सब आपके साथ लूट जाएंगे।

मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे,
खुशबू है तो हर दौर को महक आएंगे हम लोग।
हम रूह -ए - सफ़र हैं हमें नामों से ना पहचान,
कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग।

ऐ मेरे खूबसूरत एम.पी. साहिबान। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका हुस्न सलामत रहे, मेरा इश्क सलामत रहे। जिंदा रहो। खुश रहो और गरीबों की सोचो। भारत माता की, जय। वाल्मिकी महाराज की, जय।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री हंस राज हंस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदन है, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य नए हैं। मैं फिर माननीय नए सदस्य से आग्रह करता हूं कि सदन में इस तरीके से नारेबाजी नहीं की जाती। आप अपनी बात कहें।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you Speaker Ji for giving me this opportunity and I also thank the people of my constituency who have reposed faith in me and sent me here.

I have been here for the last two weeks and listening to a lot of people speaking about water crisis in various constituencies. Mostly, they are all man-

made disasters or the result of greed of some people. What I am bringing here to your notice is something totally different.

Nagarjuna Sagar dam was conceived in the year 1952. It was constructed in my constituency. During that time, the people of my constituency worked there and built it with their own hands. They sacrificed so much and thought that, at some point of time, they would also get water and some benefit from it.

(1315/AK/KDS)

The water from Nagarjuna Sagar has been used by the villagers or towns downstream, but unfortunately the Palnadu Region, where I come from, has been a drought-prone area for the last 50 years or so. If you check all the data that is available for the last 50 years, then you will come to know that every time there is a drought it is always in the Palnadu Region.

Therefore, I would request the Jal Shakti Ministry to do Varikapudisela Project, which is a lift irrigation project and which can draw water from backwaters of Nagarjuna Sagar and provide water to almost 4,50,000 households and can irrigate up to 1,20,000 acres of farm land. There is a hitch in doing this project, which is that the lift irrigation has to be done through forest areas. So, we need permission from the Ministry of Forests wherein five acres of land has to be given to this project.

I sincerely hope that both the Ministries will look into this issue and speed-up the whole project. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि मैंने व्यवस्था दी है कि कोई भी माननीय सदस्य आसन पर नहीं आए। इसके लिए मैंने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से

आग्रह किया कि वे अपने-अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे। अब कोई माननीय सदस्य, अगर आसन पर आएगा तो मुझे नाम लेकर पुकारना पड़ेगा।

श्री एस. ज्ञानतिरावियमा

*SHRI GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Long live Dr. Kalaignar. Under the able guidance of DMK leader Thalpathi Thiru M.K. Stalin, I wish to raise an important issue pertaining to Tirunelveli parliamentary constituency in this august House. This is my maiden speech in this august House. I request that the Union Government should focus on removing the wastes and carry out the cleaning work in the river Thamirabharani with a special fund allocation of Rs.500 Crore. Similar to Kumbhmela, it has been the practice of organizing Thamirabarani Pushkarani once in 144 years and it was held last year. the Union Government has been allocating funds for carrying out cleaning work of river Ganges under Namami Ganga scheme. Similarly, the Union Government should allocate Rs 500 Crore for Thamirabharani. Every year around 13.5 tmc of surplus water from Thamirabharani drains into the sea. In order to benefit water starved Tamil Nadu, particularly Tuticorin and Tirunelveli districts, the drinking water schemes should be implemented. This is the need of the hour. Thamirabharani-Karumeniyar-Nambiyar flood canal scheme should be immediately implemented providing irrigation facilities to 24000 hectares of land through 252 ponds. During the year 2009, the then Chief

* Original in Tamil

Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar M. Karunanidhi announced this flood canal scheme with an allocation of Rs. 369 Crore. The AIADMK Government which came to power thereafter kept this scheme pending for long. Now an amount of Rs 896 Crore is required for implementing this Scheme. I therefore urge upon the Union Government to immediately implement inter-linking of rivers, especially the rivers that flow through the southern part of this country. I urge that Rs 500 Crore should be allocated as a special package for carrying out cleaning work in river Thamirabharani. I urge that the Union Government should come forward to immediately implement the Thaamirabharani-Karumeniyar-Nambiyar flood canal scheme at a cost of Rs 900 Crore. Thank you.

श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हिन्दुस्तान के इस सर्वोच्च और सम्मानित सभा गृह में पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आनन्द और गौरव की अनुभूति प्राप्त करता हूँ। यह गौरव प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय श्री अमित शाह जी और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और मेरे संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ और इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ।

(1320/MM/SPR)

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के रख्याल गांव के पास से एक रेलवे लाइन गुजर रही है। रख्याल गांव में एक रोड था जो करीब 20-25 गांवों को कनेक्ट करता था। थोड़े समय पहले रेलवे वालों ने रोड को तोड़ दिया, क्योंकि कोई लैंडफिल का काम हो रहा था। हालांकि रोड रेलवे लाइन के क्षेत्र में है, लेकिन 20 से 25 गांवों को वह कनेक्ट करता है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूँ कि रोड को पुनःस्थापित किया जाए जिससे 20-25 गांवों को रोड कनेक्टिविटी मिले।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरीट पी. सोलंकी को श्री हँसमुखभाई सोमभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, this is my maiden entry in Parliament. Thank you very much for giving me this opportunity. This is the first time I entered Parliament even without entering the Assembly. I am really thankful to my hon. Chief Minister for giving me this chance.

I would like to talk about the poultry industry. As far as poultry industry is concerned, hon. President, the hon. Minister, Shri Sarangi, the Opposition leader, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and others spoke about Green Revolution, White Revolution, and Blue Revolution. But no one spoke about the poultry industry which is contributing the cheapest protein in the form of eggs and chicken to the nation. Poultry industry, which has come from the backyard farming, has grown to the extent of contributing Rs.1 lakh crore to the GDP of the country. We are the third largest egg producers, and the fifth largest chicken producers in the world. It is a self-grown industry. No one has supported the poultry industry – neither the State nor the Centre. It was for the first time, the hon. Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao has started supporting the poultry industry. After that, others followed suit. Now, a few States are supporting the poultry industry. At present, the poultry industry is in dire crisis because of absolute shortage of maize, which is the main constituent of the poultry feed.

Through you, Sir, I would like to request the Agriculture and Commerce Ministers to permit import of maize. Whenever there was a crisis in the poultry industry during 1989-90, the NAFED had supported the poultry industry by

purchasing eggs and putting them in the cold storage. Whatever losses which were incurred, the same was made good by the country and the Egg Coordination Committee. I would like to request the Ministers to also look into this issue. Thank you once again for giving me this opportunity.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महाराष्ट्र के पुणे शहर से मैं आया हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम का वंदन करके मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ।

महोदय, पुणे में गत सप्ताह कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर लोग रहते हैं, वहां 40 लोगों की मौत हुई है और मुम्बई में 20 लोगों की मौत हुई है। पुणे एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है, वहां इस तरह से मजदूरों की मृत्यु होना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को विनती करता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट और कॉर्पोरेशन के डीसी रूल में मजदूरों के लिए जो प्रबंध किया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से मजदूर आते हैं, काम करते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनायी जा रही हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के रहने के लिए जगह नहीं होती है।

मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, चाहे वह नगर परिषद हो या कॉर्पोरेशन हो, इनको ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले ही मजदूर लोगों का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि वे मेहनत से काम करते हैं, पूरा काम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन असंगठित होने के नाते उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। उनको सुरक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट रूल और डीसी रूल में सुधार करके कोई प्रबंध करना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और पुणेवासियों ने मुझे यहां भेजा है, उनको भी मैं नमस्कार करके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1325/SJN/UB)

श्रीमती दिया कुमारी (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान की बिगड़ती लॉ एंड आर्डर सिचुएशन की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। वर्तमान में राजस्थान में कानून-व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बहुत ही गंभीर एवं दुखद है। अपहरण व रेप की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ महीनों में चार-पांच घटनाएं तो मेरे ही लोक सभा क्षेत्र में घटित हुई हैं। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अधिकारियों के पास जाते हैं, तो यह सुनने को मिलता है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वे लोग यह भी कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी, तब कुछ सीसीटीवी सेंकशन हुए थे। मेरे ही एरिया राजसमन्द क्षेत्र में 400 सीसीटीवी सेंकशन हुए थे और अभी तक सिर्फ 50 ही लगे हैं। अजमेर में 800 सेंकशन हुए थे और अभी तक 132 ही लगे हैं। कंट्रोल सेंटर्स भी स्थापित नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा और बोलने दिया जाए। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह राज्य का विषय है। राज्य के विषय को आप संसद में न उठाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती दिया कुमारी (राजसमन्द): महोदय, बहुत ही गंभीर स्थिति है। मुझे आप बोलने का मौका दें... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह पहली बार है, निर्देश दे दिया है। आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती दिया कुमारी (राजसमन्द) : महोदय, ये सारी घटनाएं ज्यादातर माइन्स और वूमेन्स को साथ ही हो रही हैं। अभी जयपुर में दो दिन पहले एक माइनर के साथ एक घटना हुई थी। उसके बाद

जयपुर में धारा 144 लगा दी गई थी। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में बार-बार होती रहती हैं, हर दूसरे-तीसरे दिन अखबार खोलते ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में महिला सुरक्षा एवं आम जन सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए कि वह पुख्ता कदम उठाए, ताकि इस तरह की घटनाएं बार-बार न हों।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रामचरण बोहरा, श्री सी. पी. जोशी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अबु हसन खान चौधरी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे नए सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा कि वे यह प्रयास करें कि स्टेट सब्जेक्ट को यहां पर न उठाएं। वे यह कोशिश करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अभी जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप सभी चाहते हैं कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिले, तो सब अपनी बात को एक-एक मिनट में समाप्त करें। टू द पाइंट बोलेंगे, सब्जेक्ट पर बोलेंगे, तो सबको मौका मिलेगा। अब सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

SHRI ABU HASEM KHAN (DALU) CHOWDHURY (MALDAHA DAKSHIN): I would like to draw your attention and the attention of the Government of India to the severe problem being faced in Malda District of West Bengal.

The Malda District is famous for its varieties of mangoes. A lot of people are dependent on the mango crops for their livelihood. At present, the greatest difficulty is marketing.

In the past, our major buyers would come from East Bengal which is now Bangladesh. After Partition, 30 per cent mango growing areas went to Bangladesh. As a result, the Malda District lost its principal market. The mangoes of Malda are now sold mostly in Kolkata or in Assam. What is sold is a very small portion of what is being produced.

The problem of marketing might be solved if a food processing plant is set up in the Malda District. A food processing plant can process mangoes and make varieties of mango products. It can also bring in fruit and vegetable crops such as litchis, pineapples, oranges and tomatoes from northern districts and other surrounding districts. It would generate better incomes for the rural people of North Bengal.

(1330/KN/KMR)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, मेरठ-हस्तिनापुर रेल मार्ग स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद मानते हुए इस रेल मार्ग का निर्माण मंत्रालय टालता आ रहा है। हस्तिनापुर हमारी ऐतिहासिक व धार्मिक परम्परा का अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यह नगर वर्तमान में विश्वविख्यात जैन तीर्थ है तथा इसके निकट ही केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर सैफपुर करमचंदपुर नामक गाँव पंज प्यारे में से एक भाई धर्म सिंह का जन्म स्थान है, जहाँ विशाल गुरुद्वारा बना है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में इन स्थानों पर दर्शनार्थी आते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह रेल मार्ग आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद सिद्ध होगा परन्तु यदि वैसा हो भी, तब भी देश के दो प्रमुख अल्पसंख्यक वर्गों- जैन तथा सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करने तथा ऐतिहासिक

एवं सांस्कृतिक परम्परा में हस्तिनापुर का विशिष्ट एवं अनन्य स्थान होने के कारण मंत्रालय के सामाजिक दायित्व के नाते भी मेरठ से हस्तिनापुर की रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेष कर रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान भारत की जो सामरिक और सुरक्षा की क्षमता है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। यह सारा सदन जानता है कि भारत के एक ओर पाकिस्तान है और भारत के दूसरी ओर चीन है। पिछले नौ वर्षों में चीन अपनी सुरक्षा के ऊपर, रक्षा के ऊपर जो खर्चा करता है, वह 83 प्रतिशत से भी ज़्यादा रियल टर्म्स में बढ़ा है। उसके विपरीत भारत अपने रक्षा के ऊपर जो खर्चा करता है, वह हर साल घटता जा रहा है।

पिछले वर्ष इसी सदन की एक ऐस्टिमेट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता बहुत ही वरिष्ठ सांसद, हमारे पूर्व सांसद श्री मुरली मनोहर जोशी जी कर रहे थे, उस समिति ने एक रिपोर्ट दी कि वर्ष 2017-18 में भारत की रक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है, वह 1.60 प्रतिशत भारत की जीडीपी का है और पिछले 58 सालों में यह सबसे कम खर्चा है। जो इंटेरिम बजट सरकार ने फरवरी में पटल पर रखा था, उसमें इसकी मात्रा घट कर 1.52 प्रतिशत हो गई है। अध्यक्ष जी, यह इसलिए प्रासांगिक है, क्योंकि जो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर था, वह वर्ष 2009-10 में 45.3 प्रतिशत था। मैं एक मिनट और आपका लूँगा, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। वह पिछले वर्ष घट कर 31.28 प्रतिशत रह गया है। इस सदन की...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलना, यह बड़ा विषय है। मैं आपको मौका दूँगा।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस सदन की कई समितियों ने, रक्षा की स्थायी समिति ने, ऐस्टिमेट कमेटी ने इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृषित किया है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो वित्त मंत्री हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, मैंने आपको अभी बोलने की इजाजत नहीं दी है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): वह पहले रक्षा मंत्री थे। यह जो परिस्थिति बनती जा रही है, वे इस परिस्थिति को बजट में सुधारेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री वाई.बी. राघवेन्द्रा मैं नहीं चाहूँगा कि फिर किसी माननीय सदस्य के लिए घंटी बजाऊँ, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): Mr. Speaker, Sir, there is a digital network problem in Karnataka, especially in the rural areas. The Malenadu hilly areas and coastal regions of Karnataka are particularly badly affected with this problem. BSNL is a public sector undertaking of the Union Government. Its equipment need regular maintenance but there is a lack of supply of diesel to the generators, providing distilled water to the battery, and lack of network towers. The Union Government has launched the concept of Digital India. Under this concept, most of the young people are wholly dependent upon the digital network for their work and also for Government works. It is common now that young generations are having to leave their parents and go in search of jobs to various metro cities and settle there.

(1335/SNT/CS)

During vacation, if they intend to visit their parents, they do not get proper network to finish their day to day activities. Due to this reason, they are avoiding the visit to their parents' place.

So, hon. Speaker, Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has planned any new project to install new

mobile towers in hilly and forest areas. If not, he should give priority to these badly affected areas.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री बी.वाई. राघवेन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Hon. Speaker, Sir, Thrissur Government Medical College Hospital is the most important hospital as far as the number of patients is concerned. Patients from different parts of Thrissur, Palakkad and Malappuram are coming to this hospital by train, especially cancer patients. Therefore, I humbly submit that suburban stations such as Mulagunnathukavu and Wadakkanchery may be developed as satellite centres of Thrissur and Shornur respectively. Besides this, stoppages may be provided for the trains like Palakkad Punalur Palaruvi Express, Kochuveli Nilambur Rajya Rani Express and Trivandrum Madurai Express passing through these stations.

I also urge the Government to sanction a new passenger train from Palakkad to Palani, which is a very prominent pilgrimage destination in South India.

Thank you, Sir.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र मण्डी के अति महत्वपूर्ण सीमांत जिले लाहौल स्पीती, किन्नौर व पांगी किलाड के विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, इन जिलों का देश के अन्य भागों से वर्ष में लगभग 6 माह तक कोई सम्पर्क नहीं रहता है। सर्दियों में अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण यहाँ का तापमान मायनस 40 डिग्री सेल्सियस

तक पहुँच जाता है। इन जिलों में संचार सेवाएं भी अपर्याप्त हैं। चीन की सीमा के करीब होने के कारण यहाँ संचार सेवाओं को विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है। चाइना का मोबाइल नेटवर्क हमारी सीमा में 10-15 किलोमीटर अंदर तक पाया जाता है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनेक सराहनीय विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। इसी के परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्र की जनता ने एक बार पुनः मोदी जी को प्रचण्ड बहुमत दिया है।

महोदय, वर्तमान सरकार उत्तरी-पूर्वी सीमांत राज्यों के लिए विशेष पैकेज दे सकती है, तो हिमाचल के इन जिलों के लिए भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विशेष धन आवंटित कर, इस क्षेत्र के समग्र विकास में अमूल्य योगदान दे सकती है। विशेषकर दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल के अतिरिक्त निजी कंपनियों का भी सहयोग लिया जा सकता है। जब जनजातीय क्षेत्र के लोगों का 6 माह की बर्फबारी के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, तो केवल दूरसंचार ही एकमात्र उनका सहारा होता है, जिसके कारण वे लोग अपने सगे-संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, वहाँ बीएसएनएल व जियो के नेटवर्क से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जोड़ने की अतिशीघ्र व्यवस्था करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, the Rural Employment Guarantee Scheme better known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme plays a significant role in addressing the issue of rural distress. Millions of rural workers depend upon this scheme for their survival. The demand for increase in wages is genuine and comes from all the States. The Rural Development Ministry notified revised wage rates for 29 States and

Union Territories this year. Even after a higher budgetary allocation for MGNREGS, the hike in wages is meagre, ranging from Rs. 1 to Rs. 17 in various States. The wages paid under MGNREGS remains below the minimum wages in many States.

The Committee set up by the Union Rural Development Ministry have recommended that the wages paid to unskilled agricultural labourers under MGNREGS should be the minimum wage fixed by the respective State or the current wages as per the consumer price index for the agricultural labourers, whichever is higher.

So, I request the Government to consider the Committee's recommendations and take steps for fixing the wages accordingly.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

(1340/RV/GM)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सदन में बिना पढ़े बोलने का प्रयास करें क्योंकि पढ़ कर बोलने के लिए नियम 377 है। ज़ीरो आवर में बिना पढ़े बोलने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह खबर आई है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में तिवारे डैम दरार के कारण टूट गई है। इससे बहुत सारे लोग मर चुके हैं। बहुत बड़े इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। खबर है कि अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है, काफी लोग लापता हैं। यह भी

खबर आ रही है कि डैम की ऑथोरिटी को पहले ही चेतावनी दी गयी थी कि इस डैम की हालत बुरी है, खराब है।

माननीय अध्यक्ष: क्या यह डैम दिल्ली का है?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, अगर इसे सुधारने की कोशिश की गयी होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन में सरकार की तरफ से एक बयान पेश हो कि वहां की हालत क्या है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने मिसिंग हैं, किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, इसकी जानकारी वे सदन को दें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर कोई सदस्य राज्य के विषय के बारे में बोलते हैं तो आप कहते हैं कि राज्य के विषय के बारे में न बोलें और आप इतने बड़े नेता होकर राज्य के विषय के बारे में बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह नेशनल डिजास्टर है।...(व्यवधान) यह राज्य का विषय नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था के लिए बैठा हूँ। आपको तो व्यवस्था देने की जिम्मेदारी नहीं दी गयी है, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रना

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, first of all I would like to place on record the magnanimous decision in nominating me in the panel of chairpersons for which I express my sincere thanks.

माननीय अध्यक्ष: आप लम्बे समय तक बैठते हैं, नियम-प्रक्रिया को जानते हैं। जब आपका नाम सभापति पैनल के लिए नामित हुआ तो सभी माननीय सदस्यों ने ताली बजाई है। यह अच्छा लगता है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह भी कहिए कि वे जब चेयर पर बैठें तो हम लोगों को ज्यादा मौका दें...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Sir. I have given a notice of adjournment and my Zero Hour submission is in that regard. Two days ago, the hon. High Court of Madras had issued a judgement banning the admission of wards of poor workers on some technical grounds. The admission is going to close by 6th of July. Immediate intervention from the Ministry of Labour as well as the Ministry of Health is required. In all the ESIC medical colleges, daughters and sons of poor workers are entitled to get admission. There is 35 per cent of reservation for these ESI workers who are having the benefit under the ESIC. Unfortunately, because of the verdict of the High Court, it is being banned. So, I seek the urgent intervention of the Ministry of Labour as well as the Ministry of Health. The hon. Minister of State for Parliamentary Affairs Shri Arjun Ram Meghwal is here. I request the Government to kindly respond to this and take immediate action so as to file an appeal before the Division Bench, and if the verdict is against it, then to go to the Supreme Court so as to safeguard the interest of the poor workers' children.

माननीय अध्यक्ष: एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज सबको मौका दिया जाएगा।

श्री एम. के. राघवना

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Speaker, Sir, I would like to highlight the drawback in the provision of 10 per cent reservation for economically weaker sections as per the 124th Amendment which is affecting the people of Kerala. The norm ensuring 10 per cent reservation for economically weaker students in medical admissions may affect the chances of deserving students from the State of Kerala. Already, prospective students for NITs, IITs and IIMs have missed the opportunities. Unfortunately, the yardstick adopted while preparing the Amendment Bill was based on the social and economic situation prevailing in North India. The landholding criterion of 2.3 cents in the cities and 4.6 cents in the rural areas is the villain in this issue.

(1345/RSG/MY)

In Kerala, according to the Government standards, the minimum land requirement for construction of a house is three cents. Therefore, the minimum land holding should be increased to at least 1,500 square feet.

According to reports, under the provisions of the 124th Constitution Amendment only those children who are living in rental accommodation and who are purely landless will be benefited, leaving behind majority of the aspirants of the forward community.

The State Government of Kerala is not acting on this issue till this time. Therefore, I urge upon the hon. Ministers of Law and Social Justice to kindly intervene and re-examine the provisions of the Amendment and bring a further amendment so that the EWS children from Kerala belonging to the forward community could avail of the benefits of the 124th Amendment.

Thank you.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है और राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में पिछले कई महीनों से किसानों के साथ धोखा हो रहा है तथा उनका शोषण किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा चुनकर भेजा है। उस क्षेत्र में डेयरी और अन्य कई संस्थान हैं जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए संस्थान हैं। आज उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं। वहां कुछ ऐसे अधिकारी लगाए गए हैं, जो खुद भी एसीबी में ट्रेप हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को वहां भेजकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए बोर्ड को भंग करने का काम किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। वहां दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन करने वाले सभी किसान परेशान हैं। कलेक्टर पर हजारों किसानों ने धारणा दिया और वहां प्रदर्शन किया। वहां के किसानों और डेयरी बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। उस संस्थान को भंग करने के लिए काम किया जा रहा है। ... (व्यवधान) सुनियोजित तरीके से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसमें हस्तक्षेप करें। माननीय राहुल गांधी जी यहां नहीं हैं। उन्होंने दस दिन में कर्ज माफ करने की भी बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय, आज वहां का किसान परेशान है। वहां न तो कोई कर्जा माफ हुआ और न ही दूसरा कोई काम हुआ। वहां के किसान परेशान हैं। ... (व्यवधान) वहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे लोगों पर हस्तक्षेप करके कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, सदन का और अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

महोदय, पटना विश्वविद्यालय बिहार का ही नहीं, बल्कि देश का एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 100 वर्ष से अधिक हो गये हैं। यह पूरे भारत का सातवां विश्वविद्यालय है। यह ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है। मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत देशों में है। इस विश्वविद्यालय से निकलकर कई महापुरुषों ने देश तथा समाज की सेवा करने का काम किया है। कई राजनेता, दो राजनेता तो अभी यहां बैठे हुए हैं, एक तो श्री अश्विनी कुमार चौबे जी है, वे माननीय अध्यक्ष के रूप में वहां काम कर चुके हैं और दूसरे, श्री रविशंकर जी हैं। इसमें जय प्रकाश जी का भी कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रकवि दिनकर जी का है, साहित्यकार उषा किरण जी का है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए मैं आपका तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ।

सर, यह विश्वविद्यालय 100 वर्ष पुराना हो गया है। इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था और माननीय प्रधान मंत्री जी उसके मुख्य अतिथि थे, उसमें शिरकत किए थे। मुझे याद है, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी अभी माननीय मंत्री हैं, जब वे वर्ष 1977 में छात्रसंघ के अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूरे देश के छात्रसंघों के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय सम्मेलन कराया था और उस समय निर्णय हुआ था कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी भाई देसाई, जिन्होंने डेलीगेशन को बुलाया था, उस समय भी आश्वासन देने का काम किया गया था। राज्य सरकार ने न जाने कितनी दफा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। सर, मैं पुराना मैम्बर हूँ। मैं छह बार सांसद रह चुका हूँ। कोई ऐसा साल नहीं था, जब मैंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सदन का ध्यान आकृष्ट न करवाया हो, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो सकी।

महोदय, आज मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विशेष तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुशील कुमार सिंह, श्री बिद्युत बरन महतो तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
(1350/CP/RK)

पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है। इसमें से न निकलकर देश के अन्य भाग में ये लोग ... (व्यवधान) महोदय, अंतिम बात सुन ली जाए। मैं लगातार तीन दिन से प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी कृपा हुई, महती कृपा हुई कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह कष्ट और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। लोगों की डिमांड है, पूरे बिहार के लोगों की मन-भावना है, डिमांड है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आपकी बहुत कृपा होगी।

महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूँ कि अविलम्ब कार्रवाई की जाए और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। पूरा बिहार इसके लिए आभारी रहेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुशील कुमार सिंह, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Hon. Speaker, Sir, Vanakkam. I thank you for the great opportunity given to me to make my maiden speech in this august House.

Sir, I am a first-time Member from a humble agricultural background and I can proudly say that I am the first woman MP from Karur as well. I thank the people of Karur and the Congress Party for this great opportunity.

Karur is known for the textile industry and is the fourth largest textile exporter in the country. It is also a leading player in building bus body and mosquito net. It generates around Rs.6000 crore in foreign exchange through

export. The industry employs more than three lakh people out of which 70 per cent are women.

Through you, Sir, I would like to draw the attention of the Government to the most important crisis - the rising unemployment and the plight of the textile industry - that my constituency Karur, the Western part of Tamil Nadu and the State of Tamil Nadu as a whole is facing.

The rising competition from the neighbouring countries and the hasty implementation of GST have put the textile industry into a big stress. Also, the Basel III norm, classifying textile sector as stressed sector, has tightened the hands of the bankers and financial institutions in lending money to the textile units. Since most of the textile chains fall under MSME category, NPA-classified units are being reported every day. This leads to the closure of thousands of business houses and thus resulting in unemployment.

Recently, in Tamil Nadu 10 lakh people with higher qualifications, like MBA and M.Tech. had applied for the sweeper job. This indicates the state of unemployment that is there in the country. Aspiring young men and women are jobless. The dreams of the families and parents of a great future for their children are being shattered. Make-in-India cannot be a mere slogan. It should be implemented in letter and spirit.

I quickly come to a few solutions to revamp the industry. Most of the textile industries flourish under MSME. I urge upon the Government to introduce 20 per cent tax rate for the partnership firms with sales up to Rs.10 crore....(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati V. Geetha.

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, please allow me to finish by making only two points. Please give me one minute to suggest two or three solutions. I do not want to politicise the issue....(*Interruptions*)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य को मैं पहले भी मौका दे चुका हूँ। माननीय सदस्य सात दिन में दूसरी बार बोल रही हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): I would like to draw the attention of the Minister of Finance to the problems of more than 30,000 gold appraisers who are working with banks all over India.

Banks earn profits on the secured gold loans. The appraisers are playing a key role in disbursing loans but they do not have either job security or suitable remuneration. Banks collect appraising charges as well as processing charges from the customers. The State Bank of India is the largest public sector bank in India. Against the gold loan of Rs. 1 lakh, the SBI pays just Rs.100 to the appraisers, whereas other public sector banks pay Rs.500 for the same job. The appraisers working all over India are facing problems. I would request the Government to save these gold appraisers from the hardships that they are facing. Thank you.

(1355/NK/PS)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे सत्रहवीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मेरा विषय ब्लड शुगर स्टैन्डर्ड के संबंध में है। अभी

हाल ही में स्पेन में बड़ी-बड़ी कंपनियों की एक मीटिंग हुई थी, जो ब्लड शुगर की दवा बनाती हैं। उसमें कहा गया, अभी फास्टिंग ब्लड शुगर की लिमिट 120 है, उसको 100 कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि चालीस प्रतिशत दवा ज्यादा बिक्री होगी और देश में 70 प्रतिशत लोग बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे।

अगर हिस्ट्री देखी जाए, वर्ष 1997 में फास्टिंग में ब्लड शुगर की लिमिट 160 थी, उसको धीरे-धीरे कम करके 120 कर दी गई। मेरा कहना है कि उससे हॉस्पिटल पर प्रेशर होगा, यह मानक डब्ल्यूएचओ तय करता है। क्यों नहीं हमारे यहां इस तरह का मैकेनिज्म हो, लैबोरेटरीज हो, जिसमें हम इसको वैरिफाई करें कि उनके मानक सही हैं या नहीं? इससे कम से कम यह पता लग जाएगा। अगर 70 प्रतिशत लोग बीमार की श्रेणी में आ जाएंगे तो इससे हॉस्पिटल पर बना प्रेशर खत्म होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय कुमार, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री राहुल कस्वां और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री पी. पी. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष: आज माननीय सदस्य वकील से डॉक्टर हो गए हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): It is more dangerous when a lawyer becomes a doctor.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Doctor is saved only by a lawyer.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भारत में पीएसयूज की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर होती जा रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की चर्चा इस सदन में हो चुकी है। मैं आज इंडिया पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। आज इंडिया पोस्ट बीएसएनएल और एमटीएनएल से ज्यादा लॉस मेकिंग हो गया है, लगभग पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का लॉस हो गया है। इसके कारण वह सैलरीज नहीं दे पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार जो बजट ला रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट में लगभग पचास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने की बात चल रही है, जैसे एनटीपीसी,

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया है। इसे बेचने के बजाए इसे कैसे बचाया जाए, यह देखना चाहिए। हम चीन में देखते हैं कि चीन के स्टेट ऑनड इंटरप्राइजेज हैं वे दुनिया भर में बहुत प्रोफिट करते हैं लेकिन आज भारत पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कमजोर हो रहा है।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय अध्यक्ष, हमारे यहां रेल आवागमन को एक बहुत सस्ता माध्यम माना जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र लालगंज के रेल संबंधी समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूं। हमारा संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधान मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगा हुआ है और दूसरी छोर से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के पूर्व संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के करीब है। हमारे यहां के लोगों को अगर महानगरों या अन्य प्रदेशों में जाना हो तो काफी दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे क्षेत्र के लोगों की काफी दिनों से मांग है कि वाराणसी से लालगंज होते हुए और आजमगढ़ से गोरखपुर तक एक नई सीधी रेल लाइन का प्रबंध जल्द से जल्द से किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान देश में बढ़ रहे साइबर अपराध विशेषकर एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस नये जमाने के अपराध ने देश में पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर में पिछले दो दिनों से साइबर अपराधियों ने कई लोगों के खातों से लाखों रुपये निकाल लिए। अभी परसों 29 तारीख को एक अस्सी वर्षीय पेंशनर के खाते से 26,000 रुपये निकाल लिए। जब वह बैंक गया तो बैंक वालों ने उसे मना कर वापस भेज दिया। जयपुर में पिछले समय लगभग 36 करोड़ रुपये साइबर क्राइम के माध्यम से निकाले गए हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं।